स्वच्छता एवं नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की ओर अग्रसर हमारा प्रदेश

मीडिया संवाद

गीले कचरे से बनेगा बायो गैस, गेल इंडिया के साथ किया गया एमओयू

पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक

प्रतिदिन 150 टन क्षमता का संयंत्र

एमओयू: प्रदेश के छह नगर निगमों के ठोस अपशिष्ट से बनाई जाएगी बायो गैस

भास्कर न्यूज | रायपुर

छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू होने पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगा।

साय ने कहा कि नगरीय निकायों में इन संयंत्रों की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी। वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी। इस एमओयू से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ रोजगार भी सृजित होंगे। भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से यह कार्य पूरा होगा और इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी हमें मिलेगा। उन्होंने एमओयू में शामिल सभी संस्थाओं से संयंत्र की स्थापना के कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसी पहल से देशवासियों में अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई थी। अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस, गेल इंडिया, बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और 6 नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद थे।

इनके बीच किया गया समझौता

छत्तीसगढ़ में नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैव ईंधन बनाने की अपार संभावनाएं हैं। नगर पालिका निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु सीबीडीए, गेल एवं बीपीसीएल के साथ आज त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इनमें नगर पालिका निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा और सीबीडीए एवं गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिका निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के बीच समझौता हुआ।

स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, जीरो एमिशन की दिशा में कदम

- 6 नगर निगमों के लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिए होगा।
- 6 संयंत्रों से प्रतिदिन 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा।
- इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश पूर्ण रूप से GAIL और BPCL द्वारा किया जाएगा।
- इसी प्रकार संयंत्रों से होने वाले उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपए जीएसटी प्राप्त होगा।
- स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और नेट जीरो एमिशन की दिशा में अग्रसर होगा प्रदेश।
- संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह-उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- कचरे के प्रभावी निपटान से डीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए एमओयू

सीबीडीए, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम व 6 नगर निगमों के बीच समझौता

350 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट व 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास से बनेगा जैव ईंधन

नवभारत ब्यूरो | रायपुर

छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू होने के अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगा। नगरपालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु सीबीडीए, गेल व बीपीसीएल के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इनमें नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा तथा सीबीडीए व गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और सीबीडीए तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। एमओयू के माध्यम से इन नगर पालिक निगमों के 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट व 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में होगा। इन संयंत्रों से प्रतिदिन 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में 600 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। बायोगैस उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए का जीएसटी भी प्राप्त होगा।

पर्यावरण संरक्षण व जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

एमओयू के फलस्वरूप संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह-उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कचरे के प्रभावी निपटान से डीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सतत् योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और इसी पहल के माध्यम से देशवासियों में अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई थी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। नगरीय निकायों में इन संयंत्रों की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी।

शहर में कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट के लिए एमओयू

जैविक खाद भी होगा तैयार

पत्रिका

RAJDHANI
राजधानी 02 पत्रिका
रायपुर, शनिवार, 18 जनवरी 2025

छह नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए हुआ एमओयू

350 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास से बनेगा जैव ईंधन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में शुक्रवार को नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू हुआ। इससे 6 नगर पालिक निगमों के लगभग 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं लगभग 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिए किया जाएगा। इन 6 संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ रुपए का निवेश पूर्ण रूप से गेल इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम द्वारा किया जाएगा। इससे राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा।

इस दौरान सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और इसी पहल के माध्यम से देशवासियों में अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई थी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। नगरीय निकायों में इन संयंत्रों की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने और भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू से यह कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण होगा। एमओयू के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस., गेल इंडिया, बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और 6 नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में की बड़ी पहल : सीएम

यह होगा फायदा

- जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- कचरे के प्रभावी निपटान से ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी।
- छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा।

इनके बीच हुआ एमओयू

छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैव ईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के निरंतर प्रयास से नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिउ गेल एवं बीपीसीएल के साथ आज त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए हुआ एमओयू

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के छह नगर निगमों के बीच समझौता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया रायपुर: नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और राज्य के छह नगर निगमों के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। शुक्रवार को हुए एमओयू के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी संस्थाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। नगरीय निकायों में इन संयंत्रों की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी। उन्होंने एमओयू में शामिल सभी संस्थाओं से संयंत्र की स्थापना के कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस एमओयू से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ रोजगार भी आएंगे।

स्वच्छता व वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में बड़े निर्णय : उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में बड़े निर्णय लिए गए हैं। नगर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने और भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू से यह कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण होगा। एमओयू के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ,मुख्यमंत्री के सचिव डा. बसवराजु एस, गेल इंडिया, बीपीसीएल, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और छह नगरीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।

एमओयू के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और अधिकारी। ● डीपीआर

इनके बीच हुआ एमओयू : छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) के प्रयास से नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए सीबीडीए, गेल एवं बीपीसीएल के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इनमें नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा और सीबीडीए एवं गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और सीबीडीए, एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हुआ।

यह है विशेषता

इस एमओयू के माध्यम से छह नगर पालिक निगमों के लगभग 350 टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं लगभग 500 टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन के लिये किया जाएगा। इन छह संयंत्रों से रोजाना लगभग 70 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में लगभग 600 करोड़ का निवेश पूर्ण रूप से गेल व बीपीसीएल करेगा। उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष लगभग छह करोड़ का जीएसटी प्राप्त होगा।

नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 18 Jan 2025 - 18ra16
epaper.navabharat.news

कार्यक्रम

छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण व नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को पाने की दिशा में की है बड़ी पहल : साय

नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए एमओयू

सीबीडीए, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम व 6 नगर निगमों के बीच समझौता

350 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट व 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास से बनेगा जैव ईंधन

नवभारत ब्यूरो । रायपुर।

छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निगमों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू होने के अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगा। नगरपालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु सीबीडीए, गेल व बीपीसीएल के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इनमें नगर पालिक निगम अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा तथा सीबीडीए व गेल इंडिया लिमिटेड के बीच तथा नगर पालिक निगम बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और सीबीडीए तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हुआ। एमओयू के माध्यम से इन नगर पालिक निगमों के 350 मीट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट व 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में होगा। इन संयंत्रों से प्रतिदिन 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं में 600 करोड़ रुपए का निवेश संभिावत है। बायोगैस उत्पादन और बिक्री से राज्य को प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए का जीएसटी भी प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सतत् योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और इसी पहल के माध्यम से देशवासियों में अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई थी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। नगरीय निकायों में इन संयंत्रों की स्थापना से शहरों को स्वच्छ-सुंदर बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा। जैव ईंधन के रूप में बायोगैस के उत्पादन से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी होगी और वेस्ट टू एनर्जी की परिकल्पना भी साकार होगी।

पर्यावरण संरक्षण व जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

एमओयू के फलस्वरूप संयंत्रों की स्थापना से उत्पन्न सह-उत्पाद से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। कचरे के प्रभावी निपटान से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और छत्तीसगढ़ नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा।

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
एवं
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
छत्तीसगढ़ शासन
की गरिमामय उपस्थिति में
छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल
विकास प्राधिकरण, रायपुर
एवं
गेल (इंडिया) लिमिटेड
नगर निगम
रायगढ़

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
एवं
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव
छत्तीसगढ़ शासन
की गरिमामय उपस्थिति में
छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल
विकास प्राधिकरण, रायपुर
एवं
गेल (इंडिया) लिमिटेड

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
एवं
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
छत्तीसगढ़ शासन
की गरिमामय उपस्थिति में
छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल
विकास प्राधिकरण, रायपुर
एवं
गेल (इंडिया) लिमिटेड
नगर निगम
नगर निगम

माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय
एवं
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
की गरिमामय उपस्थिति में
WASH ROOM